भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1510

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

अर्जेंटीना में लिथियम परिसंपत्तियों की खोज

1510. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:
श्री सुखदेव भगत:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्जेंटीना में लिथियम कों की खोज करने के लिए कोल इंडिया द्वारा किए गए पहल सहित प्रारंभिक अध्ययनों की वर्तमान स्थिति तथा विचाराधीन विशिष्ट ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) के संदर्भ में अर्जेंटीना में लिथियम की खोज और संभावित निष्कर्षण को भारत के पर्यावरणीय और स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का एकल स्त्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी आपूर्ति शृंखलाओं वैविध्य लाने का इरादा है ?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अर्जेंटीना में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) : खनिज सुरक्षा भागीदारी (एमएसपी) का उद्देश्य मेजबान सरकारों और उद्योग के साथ काम करके मूल्य श्रृंखला के साथ कार्यनीतिक परियोजनाओं के लिए लक्षित वित्तीय और कूटनीतिक समर्थन की सुविधा के लिए विविध और संधारणीय महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में तेजी लाना है। एमएसपी भागीदारों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया गणराज्य, स्वीडन, यूनाइटेड

किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। एमएसपी भागीदार वैश्विक खनिज क्षेत्र में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासकीय (ईएसजी) मानकों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए कि सभी देश वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से लाभान्वित हो सकते हैं, एमएसपी केवल उन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है जो उच्च, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईएसजी मानकों को पूरा करती हैं, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देती हैं और समुदायों का उत्थान करती हैं। एमएसपी द्वारा समर्थित परियोजनाएं पूरे परियोजना जीवनकाल में कड़े ईएसजी मानकों का पालन करेंगी।

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीआईएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी को तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, नामत: नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के इक्विटी योगदान के साथ शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य भारतीय घरेलू उद्योग को इन खनिजों की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अधिग्रहण, विकास, खनन, प्रसंस्करण, खरीद और बिक्री करना है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केएबीआईएल वर्तमान में लिथियम (ली) और कोबाल्ट (सीओ) जैसी विदेशी महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के अवसरों की खोज कर रहा है और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली में परियोजनाओं में पहल कर रहा है।

अर्जेंटीना में, केएबीआईएल ने अर्जेंटीना की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के साथ एक अन्वेषण और विकास संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं और अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण और विकास के लिए विशिष्टता अधिकार प्राप्त किए हैं। केएबीआईएल ने अन्वेषण गतिविधियाँ शुरू करने के लिए आवश्यक वैधानिक निकासी और अन्य गतिविधियाँ प्राप्त करने के लिए कार्यकलाप शुरू कर दिए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में, केएबीआईएल ने ऑस्ट्रेलिया की एलआई एंड सीओ खनन परिसंपत्तियों में संयुक्त यथोचित परिश्रम और भविष्य में आगे निवेश करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के उद्योग, विज्ञान और संसाधन विभाग (डीआईएसईआर) के महत्वपूर्ण खनिज कार्यालय (सीएमओ) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केएबीआईएल को देश में लिथियम और कोबाल्ट की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक निवेश निर्णय

लेने और ऑफ टेक व्यवस्था करने में भी मदद करेगा। केएबीआईएल ने चिली में ब्राइन प्रकार के लिथियम ब्लॉक का अन्वेषण करने के लिए चिली की एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ईएनएएमआई के साथ एक एनडीए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। केएबीआईएल दीर्घकालिक निवेश के लिए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की समृद्ध क्षमता वाले अन्य देशों में संभावनाओं की खोज करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

सीआईएल ने चिली में लिथियम युक्त लवण या अन्य प्रकार के भंडारों के अन्वेषण, निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए परियोजनाओं के विकास के लिए चिली सरकार द्वारा जारी आरएफआई के प्रति अपनी रुचि की अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत की है। सीआईएल ने महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में संभावित निवेश की व्यवहार्यता की जांच के लिए विभिन्न देशों की कंपनियों के साथ गैर-प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

****